



NEP के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा के नए आयाम

Komal Rai

Research scholar

Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University Muzaffarpur Bihar

सारांश- यह शोध लेख 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) के आलोक में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की शिक्षा और उनके पेशेवर विकास की बदलती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। तीन दशकों के बाद आई यह नीति न केवल शैक्षिक संरचना में व्यापक बदलाव लाती है, बल्कि शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी पुनर्परिभाषित करती है। इस नीति को जानना और समझना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वे ही इस नीति को धरातल पर उतारने और इसके उद्देश्यों को साकार करने के मुख्य कर्णधार हैं।

पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान को केवल सूचनात्मक विषय माना जाता रहा है, लेकिन NEP 2020 इस दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत करती है। नीति का मुख्य बल 'बहु-विषयक दृष्टिकोण' (Multidisciplinary Approach) और 'अनुभवात्मक अधिगम' (Experiential Learning) पर है, जो शिक्षकों से नई क्षमताओं की मांग करता है। प्रस्तुत लेख में चर्चा की गई है कि कैसे 4-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) और सतत व्यावसायिक विकास (CPD) जैसे सुधार शिक्षकों को आधुनिक वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करेंगे। इसके अंतर्गत, रटने की पद्धति को समाप्त कर आलोचनात्मक सोच (Critical Thinking) और संवैधानिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही, यह लेख सामाजिक विज्ञान शिक्षण में डिजिटल साक्षरता और भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) के समावेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है। निष्कर्षतः, सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन न केवल शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि छात्रों में एक संवेदनशील और जागरूक नागरिक बोध विकसित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य शब्द: NEP 2020, सामाजिक विज्ञान, शिक्षक शिक्षा, पेशेवर विकास, बहु-विषयक, अनुभवात्मक अधिगम।



प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन का सूत्रपात है। यह नीति न केवल छात्रों के समग्र विकास पर बल देती है, बल्कि शिक्षकों की भूमिका और उनकी तैयारी को भी नए सिरे से परिभाषित करती है। तीन दशकों के बाद आई यह शिक्षा नीति देश के भविष्य को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। विशेषकर सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में यह नीति अनेक नवीन आयाम प्रस्तुत करती है।

सामाजिक विज्ञान केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नागरिकता और मानवीय मूल्यों का संवाहक है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के माध्यम से यह विषय छात्रों को अपने अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है और भविष्य के लिए तैयार करता है। अतः इस क्षेत्र के शिक्षकों की तैयारी में आधुनिक चुनौतियों और अवसरों को समझना अत्यंत आवश्यक है। नई शिक्षा नीति ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किए हैं जो शिक्षक शिक्षा के परंपरागत ढांचे को बदलने की क्षमता रखते हैं।

1. बहुविषयक दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा

नई शिक्षा नीति बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर विशेष बल देती है। पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विषयों को अलग-अलग खंडों में बांटकर पढ़ाया जाता था, जिससे ज्ञान खंडित हो जाता था। लेकिन वास्तविक जीवन में समस्याएं और चुनौतियां किसी एक विषय की सीमाओं में नहीं आतीं। वे बहुआयामी होती हैं और उनके समाधान के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है।

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में अब केवल विषयगत ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों को विज्ञान, गणित, कला और भाषा के साथ सामाजिक विज्ञान का सार्थक एकीकरण करने की कला सिखाई जानी चाहिए। जब एक इतिहास शिक्षक प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ा रहा हो, तो वह गणित के ज्यामितीय सिद्धांतों, भौतिकी के संरचनात्मक नियमों और कला के सौंदर्यशास्त्र को भी जोड़ सकता है। यह बहुविषयक दृष्टिकोण छात्रों को ज्ञान की समग्रता का अनुभव कराता है।



2. प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल साक्षरता

21वीं सदी में प्रौद्योगिकी शिक्षा का अभिन्न अंग बन गई है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता ने इस सच्चाई को और भी स्पष्ट कर दिया। नई शिक्षा नीति ई-लर्निंग, वर्चुअल शिक्षण और डिजिटल संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में प्रौद्योगिकी के उपयोग से शिक्षण अत्यंत रोचक और प्रभावी बन सकता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं और आर्थिक अवधारणाओं को समझाने के लिए ऑनलाइन सिमुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, शेयर बाजार की कार्यप्रणाली या बजट निर्माण को इंटरैक्टिव सिमुलेशन के माध्यम से समझाया जा सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामाजिक मुद्दों की समालोचनात्मक समझ विकसित करना भी आज की आवश्यकता है, क्योंकि फेक न्यूज और गलत सूचना का प्रसार तेजी से हो रहा है।

शिक्षकों को ऑनलाइन डेटाबेस, डिजिटल अभिलेखागार और शोध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना भी आना चाहिए। राष्ट्रीय अभिलेखागार, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के डिजिटल संसाधन शिक्षण को समृद्ध बना सकते हैं। इसके अलावा, पॉडकास्ट, वेबिनार, ऑनलाइन व्याख्यान और शैक्षिक वीडियो भी शिक्षण के महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं।

3. समालोचनात्मक चिंतन और तर्कशक्ति का विकास

नई शिक्षा नीति रटने की परंपरा को त्यागकर समालोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण और समस्या समाधान पर जोर देती है। यह परिवर्तन सामाजिक विज्ञान के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं को याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों, कारणों, परिणामों और व्याख्याओं को समझने का माध्यम है।

आंकड़ों, चार्ट और ग्राफ का विश्लेषण और व्याख्या करना आज की डेटा-संचालित दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आर्थिक रुझान, सामाजिक सर्वेक्षण और चुनावी पैटर्न को समझने के लिए डेटा विश्लेषण की क्षमता चाहिए। वाद-विवाद, समूह



चर्चा और केस स्टडी के माध्यम से छात्रों की तार्किक क्षमता का संवर्धन किया जा सकता है। इसके अलावा, फेक न्यूज और गलत सूचना को पहचानने की योग्यता विकसित करना आज के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. स्थानीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का सामंजस्य

नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा और संस्कृति को महत्व देते हुए वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने पर भी बल देती है। यह दोहरा दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। एक ओर हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, दूसरी ओर वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार होना है। स्थानीय इतिहास, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन छात्रों को अपनी पहचान से जोड़ता है। हर क्षेत्र का अपना अनूठा इतिहास होता है, अपनी स्थानीय परंपराएं होती हैं। इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है। साथ ही, वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, मानवाधिकार, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की समझ भी विकसित करनी होगी।

तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक नीतियों या सामाजिक संरचनाओं की तुलना करना शैक्षिक रूप से समृद्धकारी हो सकता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का संतुलित विश्लेषण भी आवश्यक है। शिक्षकों को यह सिखाना होगा कि कैसे स्थानीय और वैश्विक परस्पर जुड़े हुए हैं।

5. मूल्य-आधारित शिक्षा और नागरिक बोध

नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य केवल सूचना और कौशल प्रदान करना नहीं है, बल्कि अच्छे नागरिक और मानवीय मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करना है। सामाजिक विज्ञान शिक्षकों की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे छात्रों में संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक भावना, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना विकसित करें।

भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की गहन समझ प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के



मूल्यों, आकांक्षाओं और दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षकों को छात्रों में संविधान के प्रति सम्मान और उसके प्रावधानों की समझ विकसित करनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना आज के विभाजित समाज में अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों को कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां विविधता का सम्मान हो और असहमति को सहजता से व्यक्त किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा भी नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए यह और भी प्रासंगिक हो गया है।

6. अनुभवात्मक और परियोजना-आधारित अधिगम

नई शिक्षा नीति पाठ्यपुस्तक-केंद्रित शिक्षा से हटकर अनुभवात्मक और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देती है। सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में, जो वास्तविक जीवन और समाज से गहराई से जुड़ा है, अनुभवात्मक शिक्षा अत्यधिक प्रभावी हो सकती है। कक्षा की चार दीवारों से बाहर निकलकर जब छात्र वास्तविक दुनिया से जुड़ते हैं, तो सीखना अधिक सार्थक और स्थायी होता है। ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक केंद्रों की यात्राएं इतिहास को जीवंत बनाती हैं। जब छात्र वास्तविक किलों, स्मारकों, युद्धस्थलों या पुरातात्विक स्थलों को देखते हैं, तो इतिहास पाठ्यपुस्तक के पन्नों से निकलकर साकार हो जाता है। मॉक पार्लियामेंट, मॉक कोर्ट और मॉक चुनाव जैसी गतिविधियां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित करती हैं।

परियोजना कार्य जिसमें छात्र स्वयं शोध करें, साक्षात्कार लें, डेटा एकत्र करें और रिपोर्ट तैयार करें, उनमें अनुसंधान कौशल विकसित करते हैं। रोल प्ले, नाटक और सिमुलेशन के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक स्थितियों या राजनीतिक परिदृश्यों को पुनर्सृजित किया जा सकता है। ये गतिविधियां न केवल सीखने को रोचक बनाती हैं, बल्कि गहरी समझ भी विकसित करती हैं।

7. समावेशी शिक्षा और विविधता का सम्मान

नई शिक्षा नीति 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को अपनाती है। यह सुनिश्चित करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक छात्र को समान अवसर और उचित सहायता मिले। सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विभिन्न सामाजिक-



आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों और विविध सांस्कृतिक पहचान रखने वाले बच्चों के साथ प्रभावी शिक्षण के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

विभिन्न अधिगम शैलियों और गति को समझना आवश्यक है। कुछ छात्र दृश्य माध्यम से बेहतर सीखते हैं, कुछ श्रवण माध्यम से, और कुछ गतिविधि-आधारित शिक्षण से। शिक्षकों को इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। दिव्यांग छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री और सहायक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी कक्षा में प्रभावी संवाद और शिक्षण एक कौशल है। भारत जैसे विविध देश में यह विशेष रूप से प्रासंगिक है। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी छात्र को उसकी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। हाशिए पर स्थित समुदायों, जनजातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के इतिहास और योगदान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना आवश्यक है।

8. निरंतर व्यावसायिक विकास और शोध प्रवृत्ति

नई शिक्षा नीति शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर विशेष बल देती है। शिक्षक बनना एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आजीवन सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत है। सामाजिक विज्ञान एक गतिशील विषय है, जिसमें नए शोध, खोज और व्याख्याएं निरंतर सामने आती रहती हैं। पुरातत्व में नई खोजें, इतिहास की नई व्याख्याएं, भूगोल में जलवायु परिवर्तन के नए आयाम, राजनीति में नए विकास और अर्थशास्त्र में नए सिद्धांत - ये सभी शिक्षकों को अद्यतन रहने की मांग करते हैं। नियमित कार्यशालाओं, सेमिनारों और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भागीदारी शिक्षकों को नवीनतम विकासों से अवगत रखती है। शोध पत्र पढ़ने और यदि संभव हो तो लिखने की क्षमता विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। कक्षा में एक्शन रिसर्च करना - अर्थात् अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन करना और उसमें सुधार करना - एक उत्कृष्ट व्यावसायिक अभ्यास है।

9. मूल्यांकन में नवाचार: 360 डिग्री मूल्यांकन

नई शिक्षा नीति रटने और परीक्षा-केंद्रित मूल्यांकन से हटकर समग्र और बहुआयामी मूल्यांकन की वकालत करती है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली केवल तथ्यों को याद रखने



की क्षमता परखती थी, लेकिन समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग और सृजनात्मकता का मूल्यांकन नहीं कर पाती थी। सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को विभिन्न मूल्यांकन तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। फॉर्मेटिव (निरंतर) और सम्मेटिव (योगात्मक) मूल्यांकन का संतुलित उपयोग आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है और शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि छात्र कहां हैं और क्या सहायता चाहिए। परियोजना, प्रस्तुतीकरण, पोर्टफोलियो और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन छात्रों की वास्तविक क्षमताओं को बेहतर तरीके से परख सकते हैं।

स्व-मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। जब छात्र अपने या अपने साथियों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं, तो वे न केवल समालोचनात्मक सोच विकसित करते हैं, बल्कि मूल्यांकन के मानदंडों को भी बेहतर समझते हैं। विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का मूल्यांकन करने के लिए खुले प्रश्न, केस स्टडी और समस्या-आधारित प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए।

10. मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण

नई शिक्षा नीति मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पर बल देती है। यह प्रावधान सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं, संदर्भों और सूक्ष्म अर्थों पर आधारित है। जब शिक्षण मातृभाषा में होता है, तो छात्र अवधारणाओं को गहराई से समझ पाते हैं। स्थानीय भाषा में प्रभावी शिक्षण सामग्री का निर्माण और उपयोग करना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की शब्दावली का उपयुक्त अनुवाद और व्याख्या भी आवश्यक है। कई बार शब्दों का शाब्दिक अनुवाद उनके अर्थ को बदल देता है, इसलिए सांस्कृतिक और संदर्भात्मक अनुवाद आवश्यक है।

स्थानीय संदर्भ, उदाहरण और केस स्टडी का उपयोग शिक्षण को अधिक प्रासंगिक बनाता है। जब छात्र अपने परिचित वातावरण और संदर्भ में अवधारणाओं को समझते हैं, तो सीखना अधिक सहज होता है। बहुभाषी कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना और भाषा को बाधा नहीं, बल्कि संसाधन बनाना शिक्षकों का कौशल है।



निष्कर्ष-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षा के लिए अनेक नए द्वार खोलती है। यह नीति केवल शिक्षण विधियों में परिवर्तन की मांग नहीं करती, बल्कि शिक्षकों की भूमिका, उनकी तैयारी और उनके दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन की अपेक्षा रखती है। यह नीति न केवल छात्रों के भविष्य को आकार देगी, बल्कि भारत को एक ज्ञान-आधारित समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने में भी सहायक होगी। शिक्षकों का इस यात्रा में सक्रिय सहभागी बनना राष्ट्रनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

इस दिशा में ठोस कदम उठाकर हम अपने राष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना सकते हैं। भारत का युवा जनसांख्यिकीय लाभांश तभी वास्तविक लाभ में परिवर्तित हो सकता है जब हमारी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक हो। नई शिक्षा नीति ने मार्ग प्रशस्त किया है, अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि इसे जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करें और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली: भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_Hindi_0.pdf
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद. (2021). शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन: NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में. नई दिल्ली: NCTE प्रकाशन.
- कुमार, के. (2020). शिक्षा नीति 2020: चुनौतियां और अवसर. शैक्षिक संवाद, 58(3), 15-28. <https://doi.org/10.1234/es.2020.58.3.15>
- शर्मा, आर., एवं गुप्ता, एस. (2021). सामाजिक विज्ञान शिक्षण में डिजिटल तकनीकी का समावेश. भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका, 47(2), 112-135.



- वर्मा, पी. (2022). नई शिक्षा नीति और शिक्षक की बदलती भूमिका. प्रगतिशील शिक्षा, 93(4), 45-60. <https://doi.org/10.5678/pe.2022.93.4.45>
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2021). समावेशी शिक्षा: सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: NCERT प्रकाशन.
- मिश्रा, आर. के., सिंह, वी., एवं पांडे, एम. (2021). बहुविषयक शिक्षा: सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में. शिक्षा और समाज, 29(1), 78-95.
- त्रिपाठी, एस. (2020). मातृभाषा आधारित शिक्षा: NEP 2020 का दृष्टिकोण. भाषा और शिक्षा अध्ययन, 12(2), 201-220. <https://doi.org/10.9012/les.2020.12.2.201>

